

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: नवाचार और चुनौतियाँ

डॉ० रुबी

सहायक आचार्य,
समाज कार्य विभाग,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
ई मेल: rubee@jncu.ac.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्तमान भारत की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक रूप प्रदान करना है। यह शोध पत्र एनईपी 2020 द्वारा पेश किए गए प्रमुख नवाचारों और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पता लगाता है। नई शिक्षा व्यवस्था में बहु-विषयक शिक्षा का एकीकरण, पाठ्यक्रम में लचीलापन, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और रटने की शिक्षा में बदलाव शामिल हैं साथ ही वैश्विक रुझान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह नीति बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीवन सीखने पर भी जोर देती है। इसके अलावा, यह एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो पहुँच और लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित करती है।

इन नवाचारों के बावजूद, एनईपी 2020 को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध पत्र में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का अध्ययन किया गया है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और शहरी और ग्रामीण शिक्षा प्रणालियों के बीच असमानता, डिजिटल विभाजन और नए शैक्षणिक तरीकों की जटिलता पर केन्द्रित किया गया है। यह अध्ययन नीति की सफलता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें भाषाई विविधता और क्षेत्रीय असमानताएँ शामिल हैं।

इन नवाचारों और चुनौतियों का विश्लेषण कर, यह शोधपत्र भारत की शिक्षा प्रणाली पर NEP 2020 के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने का एक प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक व्यापक योजना है। इस नीति से पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे 1992 में संशोधित कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया था किन्तु समय के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां महसूस की गयी जिसके परिणामस्वरूप NEP 2020 की नींव रखी गयी का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली की बदलती और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक समग्र और आधुनिक बनाना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।

एनईपी 2020 जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षण सुविधाएं तथा प्रशिक्षण सम्बंधित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया। इस नीति के अंतर्गत शिक्षा के जिन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव किया गया वह इस प्रकार है, -

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अंतर्गत बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE Early Childhood Care And Education) पर विशेष बल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 8 वर्ष तक के बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों में उत्तरदायी देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास में संतुलन स्थापित हो तथा बच्चों का चहुमुखी विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त ECCE के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उनकी सीखने की क्षमताएं और कौशल मजबूत हों, और उन्हें भविष्य की शिक्षा के लिए एक सशक्त आधार प्राप्त हो सके।
- नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए, चाहे वे कहीं भी रहते हों, सीखने के नए तरीकों का निर्माण, उनके सुव्यवस्थित क्रियान्वयन और प्रभावी रूप से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ माता-पिता और समुदायों को भी शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त, यह स्कूलों और शिक्षकों का समर्थन करने पर भी बल देती है। सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर और उसमें सुधार करके, एनईपी 2020 देश के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने की आशा करता है, ताकि हर बच्चा सफल हो सके और समाज में अपना योगदान दे सके।
- नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण से सुधारना है, जिससे छात्रों के लिए सीखना और अधिक व्यापक हो सके। छात्र एक ही विषय तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को समझेंगे। उदाहरण के लिए, विज्ञान के पाठ्यक्रम में गणित और कला को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों में यह समझ विकसित होगी कि सभी क्षेत्र वास्तविक जीवन में एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इस बदलाव को सफल बनाने के लिए, स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में आवश्यक सुधार किया गया है। शिक्षकों को नए और रुचिकर तरीके अपनाने में सहूलियत देने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिससे छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया अधिक आकर्षक और रुचिकर हो सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में मातृभाषा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है। भाषायी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इस नीति के तहत यह सुविधा भी दी गयी है कि बच्चे अपनी मातृभाषा अथवा अपनी स्थानिय भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े रहेंगे तथा शिक्षा को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे क्योंकि विभिन्न शोधों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में चीजों को जल्दी समझते हैं और ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात कर पाते हैं। इसके साथ ही, बहुभाषावाद से बच्चों में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान और रुचि बढ़ती है। इस नीति के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, और धीरे-धीरे दूसरी भाषाओं का भी समावेश किया गया है, ताकि बच्चों में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास भी हो सके और वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।
- यह शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है साथ ही यह छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखती वरन् उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल से भी जोड़ने का बढ़ावा देती है, जिससे छात्र अपने भविष्य की योजना बना सके तथा अपने रुचि अनुसार रोजगार हेतु तैयार हो सकें।

नीति के अनुसार, माध्यमिक स्तर से ही छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर दिए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कोडिंग, शिल्पकारी, कृषि, कारीगरी, एवं अन्य व्यवसायिक कार्य शामिल किये गये हैं, जिन्हें सीखाने हेतु आधुनिक तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है, जिससे न केवल युवाओं को रोजगार हेतु तैयार करने में सहायक है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

- नई शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचार को बढ़ावा देकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इस नीति के तहत, शोध-उन्मुख शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं, ताकि छात्रों में जिज्ञासा, सृजनात्मकता, और समस्या-समाधान के कौशल का विकास हो सके इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में नया ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन कोर्स को प्रोत्साहित किया जा सके तथा अनुसंधान कार्य हेतु संस्थानों में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके।

नीति के अंतर्गत, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया (RFI) की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में अनुसंधान हेतु धन, ढांचगत व्यवस्था एवं सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही, छात्रों को उनके क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और तरीकों से अवगत कराने के लिए उद्योगों और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रयास न केवल छात्रों को उनके क्षेत्रों में गहरी समझ देगा, बल्कि उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप शोधकर्ता और उद्यमी बनने में भी सहायक होगा।

- इस ढांचे के तहत संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और प्रबंधन में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता के मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को भी लागू किया गया है। इस नीति में पहली बार शिक्षा प्रणाली में समस्त हितभागियों को जैसे अभिभावक, छात्र, पूर्व छात्र, शिक्षक एवं उद्यमियों को पाठ्यक्रम एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है जिससे सभी हितधारकों को शिक्षा प्रणाली में सामूहिक भागिदारी को बढ़ाया जा सके और वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति जागरूक हो सके।

इसके अतिरिक्त इस नीति के तहत पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली और डेटा साझा करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) की भी बात की गयी है। जिसमें छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन डेटा-आधारित मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत फीडबैक पर आधारित है। डेटा-आधारित मूल्यांकन के तहत AI आधारित सॉफ्टवेयर छात्रों के प्रदर्शन का डेटा संग्रहित और विश्लेषित कर सकते हैं, जिससे शिक्षकों को वास्तविक समय में छात्रों की प्रगति को समझने में मदद मिलती है। वही दूसरी तरफ व्यक्तिगत फीडबैक का प्रयोग छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों के आधार पर व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान किया जा सकता है, जिससे वे अपने अध्ययन की दिशा में सुधार कर सकें। इस प्रकार इस पहल से न केवल शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में एक जिम्मेदार और उत्तरदायी माहौल भी विकसित होगा, जो छात्रों के लिए अधिक प्रभावी और लाभकारी होगा।

- नई शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में समता और समावेशन को बढ़ावा देना है। नीति के तहत इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को समान

एवं उच्च स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके तथा शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षिक अधिकारों में किसी भी स्तर पर विद्यार्थियों को भेदभाव का सामना न करना पड़े। इस नीति के तहत, वंचित समुदायों, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों, लड़कियों और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस नीति में छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, लचीली और सुलभ शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए छात्रों को मुफ्त शिक्षण सामग्री, छात्रवृत्ति, और डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर बल दिया गया है। साथ ही, समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को समान अवसर और समर्थन दे सकें।

- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, और उनके व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में शिक्षा प्रणाली में सक्षम, कुशल और प्रेरित शिक्षक को शामिल करने का ध्येय रखा गया है, जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हों अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नीति के अंतर्गत, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने, योग्यता-आधारित और दक्षता-केंद्रित बनाने के लिए नए-नए मानक तय किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, अध्यापकों में शिक्षण कार्य को और कुशल बनाने हेतु उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। नीति में शिक्षकों के करियर विकास के लिए भी स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नति और मान्यता दी जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लाने के लिए पेश की गई है। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढाँचा (स्कूल भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और कक्षाएँ) अभी भी कमजोर हैं। NEP 2020 में प्रस्तावित कई सुधारों के लिए तकनीकी और डिजिटल संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन पिछड़े जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- NEP 2020 के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बहुत सीमित है। इससे डिजिटल डिवाइड की समस्या पैदा हो रही है, जिसके कारण पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा तक पहुँचने के समान अवसर नहीं मिल रहे हैं और वे नए तकनीकी उपकरणों के उपयोग से वंचित हो रहे हैं।
- एनईपी 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों— शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हालांकि, पिछड़े क्षेत्रों में न केवल छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं है, बल्कि अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं।
- एनईपी 2020 के तहत छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता है। हालांकि, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। संसाधनों की कमी के कारण छात्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

- एनईपी 2020 के तहत सबसे बड़ी चुनौती छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि की कमी है। पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं का एक ही लक्ष्य है— डिग्री हासिल करना। वे कक्षाओं में भाग लिए बिना ही पास होना चाहते हैं। ऐसे में छात्रों में ज्ञान और समझ का स्तर कम होता जा रहा है, जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन रहा है।
- पाठ्यक्रम में विषय-वस्तु की अधिकता और लगातार सेमेस्टर परीक्षाओं के कारण छात्रों में विषय-वस्तु को समझने और आत्मसात करने के बजाय उसे रटने की आदत पड़ रही है। अपने सीजीपीए को बेहतर बनाने के लिए उनमें नकल करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।
- इस नीति के तहत छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, पर्याप्त करियर परामर्श और मार्गदर्शन की कमी के कारण छात्र अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और उचित विचार किए बिना ही पाठ्यक्रम चुन लेते हैं। नतीजतन, एक कोर्स पूरा करने के बाद, उन्हें अपने अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित नौकरी खोजने या व्यवसाय शुरू करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उन्हें दूसरे कोर्स में फिर से दाखिला लेना पड़ता है, इस उम्मीद में कि किसी दूसरे क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने से नौकरी पाना आसान हो जाएगा। नतीजतन, कई भ्रमित छात्र कई विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करते हैं, जिससे उनके उत्पादक वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार जो उस युवा का उत्पादक वर्ष है जिसमें वह अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में अर्थात् अपने आजीविका में अपना समय लगा सकता था, वह युवा अपने महत्वपूर्ण समय को व्यय कर छात्र जीवन व्यतीत करने में अपना अनावश्यक समय लगा देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 8 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करना है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास संतुलित हो सके। नीति सभी बच्चों के लिए नए सीखने के तरीकों का विकास, माता-पिता और समुदायों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा को समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण से सुधारने का प्रयास किया गया है, जिससे छात्र विभिन्न विषयों के बीच संबंध समझ सकें। मातृभाषा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देकर बच्चों को उनकी सांस्कृतिक पहचान से जोड़े जाने पर भी जोर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और शिक्षा में समता और समावेशन को सुनिश्चित करना भी नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। इसके तहत, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए गए हैं, जिससे योग्य और प्रेरित शिक्षक तैयार हों। इस नीति का लक्ष्य सभी छात्रों को समान और उच्च स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए सक्षम बन सकें किन्तु जहां एक ओर नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करती है वहीं दूसरी तरफ इस नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ का भी समाना करना पड़ रहा है। नीति के क्रियान्वयन में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षिक ढाँचा और डिजिटल संसाधनों की कमी से डिजिटल शिक्षा का विस्तार कठिन हो रहा है, जिससे डिजिटल विभाजन बढ़ रहा है और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। एनईपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रशासन और निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन रुचि की कमी और संसाधनों की कमी से छात्रों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। नीति में छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी दी गई है, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में वे भ्रमित हो जाते हैं और कई बार उचित निर्णय लेने में असफल रहते हैं। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष आने वाली इन चुनौतियों को दूर करने के पश्चात् नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

- Bhargava, S. (2021). A critical analysis of NEP 2020: Opportunities and obstacles. *Policy Perspectives*, 9(1), 101–106.
- Drishti IAS. (2020). *National Education Policy 2020*. <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/national-education-policy-2020>
- Kapur, D., & Misra, P. (2021). Implementation challenges of NEP 2020: A review. *Journal of Education and Social Policy*, 28(2), 12–23.
- Kumar, K. (2020). Impact of National Education Policy 2020 on higher education. *Journal of Education and Practice*, 11(34), 1–6.
- Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2022). *Implementation of National Education Policy 2020: School education*. NCERT.
- Press Information Bureau. (2022). *National Education Policy updates*. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847066>
- Ramanathan, L. (2021). Language policy in NEP 2020: Implications for linguistic inclusivity in India. *Indian Linguistics Review*, 39(1), 33–36.
- Rao, M., & Shukla, A. (2020). The impact of NEP 2020 on higher education in India. *International Journal of Education Reform*, 15(3), 145–151.
- Sharma, N., & Patel, V. (2020). NEP 2020 in a global context: Parallels with Finland and Singapore. *Global Journal of Comparative Education*, 14(2), 78–82.
- Sharma, P., & Gupta, N. (2021). A critical analysis of National Education Policy 2020. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 8(1), 45–50.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- Vikaspedia. (2020). *National Education Policy 2020*. <https://vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/national-education-policy-2020>
- World Bank. (2021). *Education policy and reforms in India: Insights on NEP 2020*. World Bank Publications.
- BYJU'S. (2020). *National Education Policy 2020*. <https://byjus.com/free-ias-prep/national-policy-education/>



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

R
S
E
A
R
C
H
G
A
T
E
W
A
Y

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



A
R
O
G
Y
A
M
O
N
L
I
N
E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER



COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



- BLUE** Calms your Child's Mind & Body
- YELLOW** Promotes Concentration, Stimulates the Memory
- PINK** Evokes Empathy, makes your Child Calm
- RED** Excites and energizes your Child's body
- GREEN** Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE